

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

757042
24-4-15

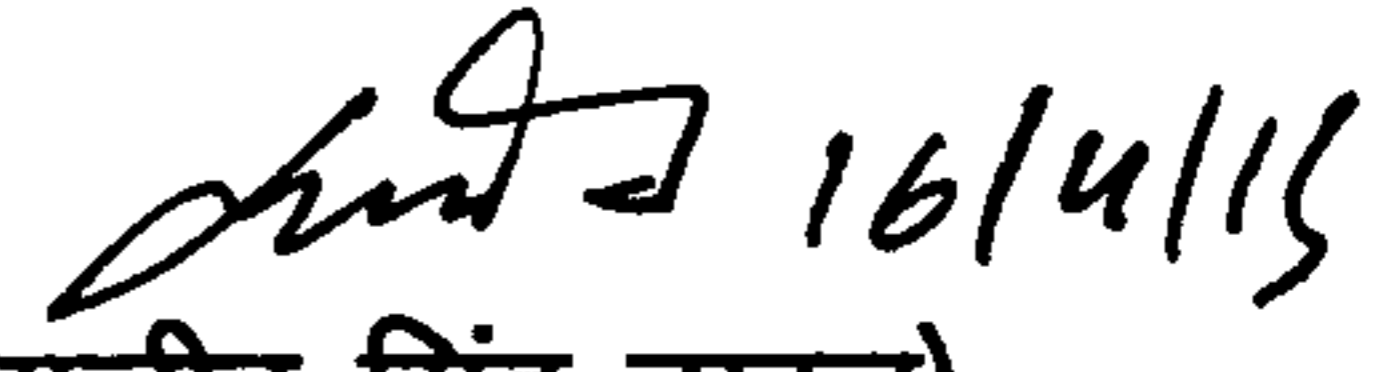
क्रमांक: एफ.-27(44)ग्राविवि/ग्रुप-5/आवास/प्रगति/समीक्षा/2015-16 दिनांक: 16 अप्रैल, 2015

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.)
राजस्थान, जयपुर

विषय : वर्ष 2011-12 के स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में ।

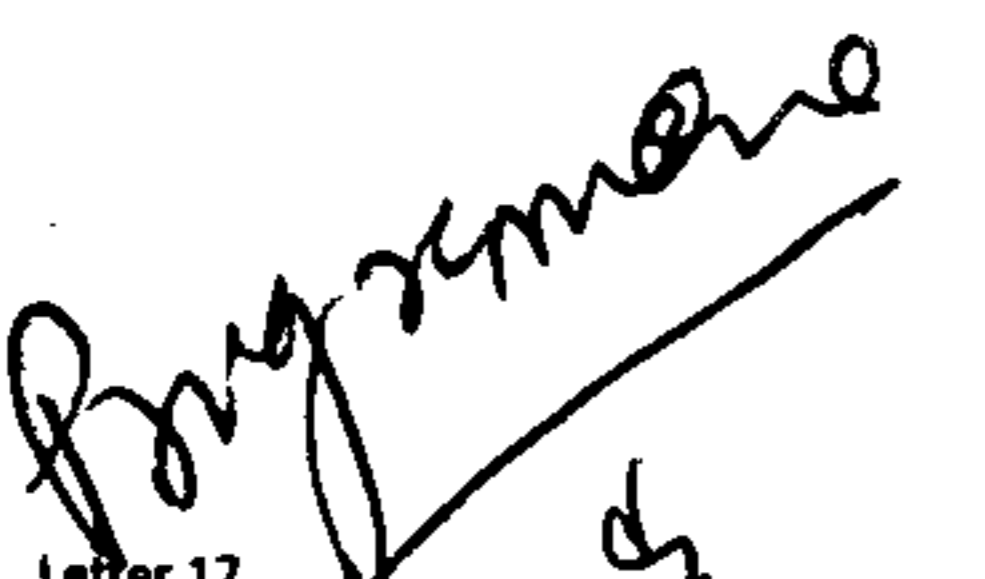
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इन्दिरा आवास योजना क्रियान्वयन के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृत आवास को पूर्ण कराने हेतु अधिकतम 2 वर्ष एवं विशेष परिस्थितियों में 3 वर्ष अनुमत है । वर्ष 2011-12 में स्वीकृत इन्दिरा आवासों को पूर्ण कराने हेतु अनुमत अधिकतम 3 वर्ष की समय सीमा माह मार्च 2015 में ही समाप्त हो चुकी है ।

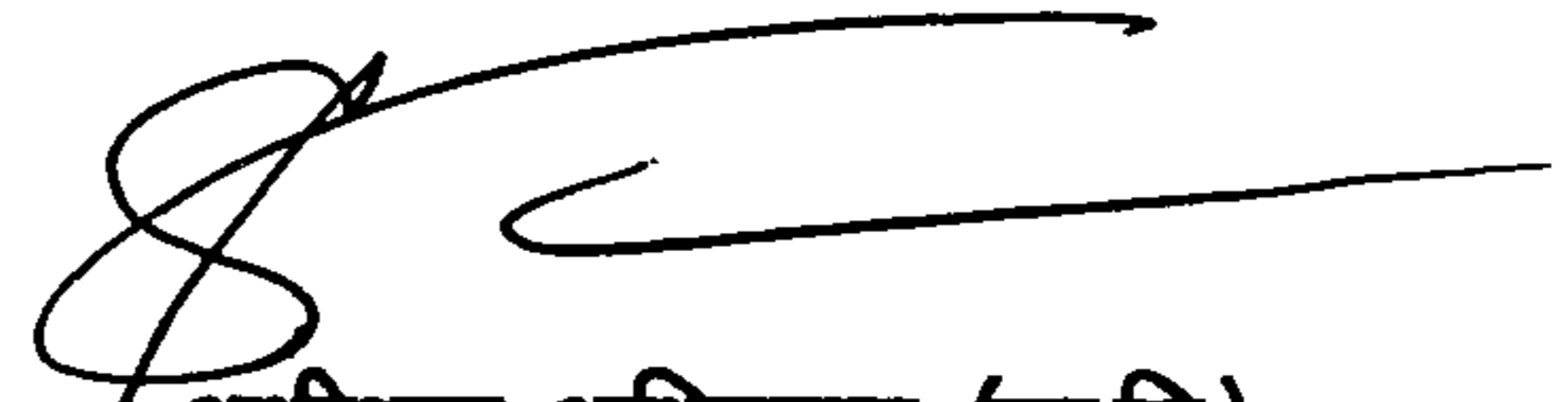
भारत सरकार को वर्ष 2015-16 में आवंटित लक्ष्यों की राशि व पूर्व के वर्षों के स्वीकृत आवासों की राशि की किश्त प्राप्त करने हेतु इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि वर्ष 2011-12 में स्वीकृत सभी इन्दिरा आवास पूर्ण कर लिए गये है । अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2011-12 व 2012-13 में स्वीकृत सभी योजनाओं के आवासों को 30.06.015 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें । समय सीमा तक यह कार्य पूर्ण नहीं होने पर राज्य सरकार को किश्त प्राप्त न होने अथवा विलम्ब होने की स्थिति में आप व्यक्तिगत जिम्मेदार होंगे ।


(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रावि एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा स्कीम, राजस्थान, जयपुर ।
6. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो. एवं मू.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत ।
8. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान, जयपुर ।
9. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजस्थान, जयपुर ।


Letter 17
23/4


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रा.वि.)